Situation Arising out of Floods in Bihar

श्री जगदम्बी मंडल (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलने के पूर्व आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस सदन में पहली बार मैं आया हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मध्याह्न पूर्व उपसभापति महोदया ने इस सदन को सूचित किया था कि बाढ़ पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। मैंने बाढ़ पर बोलने की सूचना दी थी इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे उस चर्चा में भी शामिल करने की आप कृपा करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे तो संपूर्ण भारत में बाढ़ पर प्रति वर्ष चर्चा होती है, इससे होने वाली जान-माल की क्षति पर भी चर्चा होती है किन्तु मैं संपूर्ण देश की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बिहार की बात करूंगा और बिहार में भी उत्तर बिहार की नदियों में से कोसी नदी की बाढ़ की चर्चा करूंगा। महोदय, हमारे बिहार के जितने सांसद हैं, उन्हें पूरी तरह मालूम है कि कोसी नदी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार के सहयोग से एक बहुत बड़ा जलाशय आज से बहुत वर्ष पूर्व बनाया था। सरकार की मंशा थी कि कोसी नदी की बाढ़ से जो विनाश लीला होती है, उसे नियंत्रित किया जाए। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी विनाश लीला के बाद भी यह बाढ़ नियंत्रित नहीं हो सकी। जो अभिशाप शुरू में था और जो वरदान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। मैं पिछले शनिवार को वहां गया हुआ था, उससे पहले भी 13 शनिवार को गया हुआ था, उस समय नदी में बाढ़ कम थी। एक गांव था जो कि कट रहा था, वहां भीषण कटाव था। मैं उस गांव को देखने गया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे देखकर हैरत हुई कि लोग परेशान होते हैं, घर बनाने के लिए व्यस्त रहते हैं। उस गांव के लोग घरों को उजाड़ने में व्यस्त थे, किसी को फुर्सत नहीं थी, घर कट रहा था। लोग घर की ईटों को, घर के छप्परों को उजाड़ने में मशगूल थे। उनके लिए बड़ी दर्दनाक स्थिति थी कि कहां बसेंगे? और उसके ठीक सात दिन बाद जब मैं पुनः 20 तारीख को खगड़िया गया तो देखा कि बिहार का एक जिला खगड़िया अन्य जिलों की तरह कोसी नदी की बाढ़ से पीड़ित है। वैसे तो उस नदी से अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा आदि अनेक जिले प्रभावित हैं, लेकिन उसमें खगड़िया अत्यधिक प्रभावित हुआ है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सात दिन पूर्व जब मैं वहां आया था तो नदी की कोई विनाशकारी लीला नजर नहीं आती थी सिर्फ एक गांव के कटाव को छोड़कर। लेकिन उस दिन, उस समय समूचा प्रखण्ड, जिला सिर्फ खगड़िया जिला ही नहीं, खगड़िया जिले के पूर्व में मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर आदि पानी से लबालब भरे थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि समुद्र इन्हीं जिलों में चल पड़ा है। वहां के लोगों की दुर्दशा को देखा, उनके घर में पानी घुस गया और लोग अपना घर-बार छोड़कर ऊंचे टीलों पर जाने लगे। हमने देखा कि कोई सड़क के किनारे बसा हुआ है, कोई आदमी ऊंचे टीले पर आश्रय लिये हुये है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस उद्देश्य से आपने कोसी नदी पर डेम बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति संकल्प के साथ होनी चाहिए। वैसे तो हर वर्ष बाढ़ आती है और सरकार सहायता करती है। हर जनतांत्रिक देश में लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह संकट के समय में हमारी सहायता करे। लेकिन सरकार तब सहायता करती है जब बाढ़ खत्म हो जाती है। बाढ़ के उचित समाधान के लिए, दीर्घकालीन समाधान के लिए सरकार उपायों को भूल जाती है और पुनः जब बाढ़ आती है तब उसको ख्याल आता है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सारे जिलों की बर्बादी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार सहायता करे क्योंकि राज्य सरकार संसाधनों के अभाव में काम नहीं कर पाती है। मैं भारत का नागरिक हूं और वहां के जिलों के लोग भी भारत के नागरिक हैं। वहां के जिलों के लोगों की अपेक्षा है कि यदि राज्य सरकार को इसमें सफलता नहीं मिलती है तो भारत सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेकर उस नदी के पानी को नियन्त्रित करे। यहां पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र जी नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): हम बाढ़ को लेकर विशेष चर्चा करेंगे, उस समय आप विस्तार से बोलिएगा।

श्री जगदम्बी मंडल: एक मिनट और मेरी राय में और मेरे द्वारा पूछे गये विशेषज्ञों की राय में उस नदी के जल का जो तल है वह सिल्टिंग के कारण ऊंचा होता जा रहा है। सिल्टिंग होने से यह नदी अपने रास्ते को छोड़ कर के दूसरे रास्ते में चली जाती है और अगल-बगल के गांवों को काटकर खत्म कर देती है। मैं दो चार जिलों के दो-चार गांवों का नाम भी बता देना चाहता हूं। मधेपुरा जिले के एक गांव का नाम करारिया

है और भागलपुर जिले के गांव का नाम विसपुरिया है और उसके भी नजदीक एक बस्ती है।

खगरिया जिले का इदमादी, पौड़ा, बसुवा, चोढ़ली, अनेक गांव कोसी नदी की गर्भ में चले गये हैं और आज तक उन लोगों के कहीं रहने की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि समय रहते इसकी उचित व्यवस्था कराई जाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप संक्षिप्त में बात करना रामदेव भंडारी जी।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): महोदय, दो-चार लाइनें ही बोलूंगा। महोदय, मैं माननीय सदस्य, जगदम्बी मंडल जी, जिन्होंने विशेष उल्लेख के द्वारा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति की चर्चा की है, अपने आपको एसोसिएट करता हूं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल हम इसी सदन में उत्तरी बिहार की बाढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ी-बड़ी नदियां कोसी, कमला, गंडक महा-नन्दा और बागमती उत्तरी बिहार में हैं। ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं और कई बार हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया कि नेपाल सरकार के साथ एक समझौता करके इसका स्थाई समाधान निकाला जाये मगर वह समाधान अब तक नहीं निकला है।

पिछले दिनों दूरदर्शन पर एक समाचार सुनने का मौका मिला जिसमें नेपाल के कोई मंत्री पटना में बोल रहे थे। शायद भारत सरकार के साथ निकट भविष्य में कोई समझौता होने जा रहा है और वे अपने क्षेत्र नेपाल में बांध बनायेंगे। अगर नेपाल में बांध बन जाता है तो ये जो बाढ़ की विभीषिका है, ये जो बड़ी-बड़ी नदियां नेपाल से भारत में आती हैं जो अपने साथ हर साल बाढ़ लाती हैं उस पर नियंत्रण हो सकता है।

महोदय, एक सेंट्रल कैलामिटी रिलीफ फंड केन्द्रीय सरकार के पास है, उस फंड से बिहार सरकार का जो एनुअल एलोकेशन है वह 51.96 करोड़ है। आंध्र प्रदेश सरकार का एलोकेशन 124.19 करोड़ है, गुजरात का 139.60 करोड़ तथा राजस्थान का 179.04 करोड़ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ से नुकसान होता है हर साल, उसी लिहाज से जो एन्यूवल एलोकेशन 51.96 करोड़ का है, वह बहुत ही कम है उसमें से भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर 38.96 करोड़ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको विस्तार से बात करनी है तो जब हम लोग बाढ़ के ऊपर बात करेंगे तब करना। आप तो पुराने सदस्य हैं।

श्री जगदम्बी मंडल: मैं दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि केन्द्रीय सरकार यहां से एक सेन्ट्रल टीम भेजे जो उत्तरी बिहार में जाकर एसेस करें कि वहां बाढ़ से कितनी क्षति हुई है और जो क्वार्टरली फंड रिलीज होता है, अभी तक 198 करोड़ रिलीज हुआ है। एक तीसरे क्वार्टर का जो फंड होगा कैलामिटी रिलीफ फंड, वह तुरन्त रिलीज करें केन्द्रीय सरकार और वहां टीम भेजी जाये, इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (मोहम्मद सलीम): राज गोपाल। ...(व्यवधान) काफी बात आपको भी....व्यवधान) यह काफी बड़ी बात है।

श्री नरेश यादव (बिहार): हमारा जिला कटिहार भी बाढ़ से काफी प्रभावित है और यह नियति हो गई है कि बाढ़ आना, उससे भूमि कटाव होना तथा किसानों की भूमि बर्बाद होना। इसलिए हम यह कहेंगे कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अधिक से अधिक राशि देकर पक्की, सुदृढ़ व्यवस्था भूमि कटाव व बाढ़ नियंत्रण पर लगानी चाहिए और केन्द्रीय टीम को वहां भेजना चाहिए। इसी के साथ मैं जगदम्बी मंडल जी के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। धन्यवाद।

Neglect of Adi Shankara Sanskrit University, Kerala

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opoprtunity. I would like to invite the attention of the Government of India, through you. Sir, to the way in which the Government of Kerala is trying to strangulate the Sanskrit University established in the name of Adi Shankaracharya in Kaladi. So, an agitation has been launched by students today throughout Kerala. Recently, the university syndicate also met and registered their protest against the way in which this strangulation is going on. The Government of Kerala apparently does not believe in encouraging Sanskrit. Therefore, they want to strangulate it in some way or the other. Last year the Government of Kerala had allotted Rs.